सांध्य दैनिक
4PM
www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्षः 11 ● अंकः 52 ● पृष्ठः 8 ● लखनऊ, बुधवार, 26 मार्च, 2025
मूल्य ₹ 3/-
जिद...सच की

इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार-बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता।
-कबीर दास

जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे केकेआर... 7 | नहीं थम रहा महाराष्ट्र में विवादों... 3 | पिछड़ों के प्रति केंद्र व राज्य... 2

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का राजनीतिक यूटर्न!

मुस्लिमों को भाजपा की सौगात

विपक्ष ने उठाए सवाल

किट में मिलेंगे सेवाइयां, चीनी, बेसन सूजी, मेवे, कपड़े

ईद पर 32 लाख मुसलमानों में बांटेगे मोदी किट

» सलमान की फिल्म सिकंदर और पीएम मोदी की सौगात इस ईद को बना रही है खास

» बिहार चुनाव को फोकस कर बनाया गया है प्रोग्राम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश में इस ईद कुछ नया होने जा रहा है, ईद पर सलमान खान की फिल्म सिकंदर के साथ चर्चा पीएम मोदी की गरीब मुसलमानों को बंटने जा रही सौगाते मोदी किट की है। दोनों ही चीजों ने पब्लिक डोमेन में तहलका मचा रखा है। जितनी चर्चा सलमान की फिल्म सिकंदर की हो रही है उतनी ही चर्चा मोदी किट की भी हो रही है।

जानकारी के मुताबिक इस किट में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरूषों के लिए 500—600 रूपये कीमत का सामान है। इस कार्यक्रम को बिहार चुनाव को फोकस करते हुए बनाया गया है। इस किट को 32 लाख मुसलमानों के बीच वितरण किया जाएगा। विपक्ष ने सवाल पूछा है कि पीएम मोदी की सौगात सिर्फ मुसलमानों को ही क्यो? दूसरे अन्य त्योहारों मानने वाले लोगों को इस तरह की किट का वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है।

पहली बार खास मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की सौगात-ए-मोदी किट

कुछ भी कर सकती है बीजेपी : अखिलेश

विपक्षी ने सौगात-ए-मोदी किट वितरण कार्यक्रम को वोट पाने की रणनीति करार दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म के हों। अखिलेश यादव ने कहा कि यह खुशी की बात है कि बीजेपी अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। उन्होने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।

500 से 600 रुपये की कीमत

ईद के मौके पर जो सौगात-ए-मोदी किट दी जा रही है, उसमें ईद के त्योहार के लिए मुस्लिम परिवारों को किट में सेवाइयां चीनी, बेसन, सूजी, मेवे और परिवार की एक महिला के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं। सिख और ईसाई परिवारों के लिए किट अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि उनके पर्वो में अभी समय शेष है। उनकी किट में त्योहार के लिए जरूरी चीजों को शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, तैयार की गई प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500-600 रुपये है।

राजद ने बताया ठगी की किट

जिस बिहार को फोकस कर किट बांटी जा रही है। उसी बिहार से सबसे पहले इस किट पर बड़ा आरोप लगा है। राजद नेता और पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर ने इसे ठगी की किट बताया है। राजद नेता और पूर्व मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने ईद के मौके पर दिए जाने वाले सौगाते-ए-मोदी को ठगी किट बताया है। उन्होंने कहा, यह ठगी किट होगा। वे लोग घूस देने में माहिर हैं।

ऊंट के मुह में जीरा

सौगाते मोदी किट वितरण कार्यक्रम की शुरूआत दिल्ली के निजामुददीनऔलिया क्षेत्र से हो चुकी है। अब इस कार्यक्रम को बिहार पहुंचना है जहां चुनाव सर पर है। विपक्ष ने इस वितरण कार्यक्रम पर उंगलिया उठाई है और इसे सीधे राजनीतिक हित को साधने वाला कार्यक्रम बताया है। जबकि बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास वाले बीजेपी के मूल नारे से बता रही है। मुस्लिम बुद्धजीवी इसे ऊंट के मुह में जीरा जैसा बता रहे है क्योंकि देश में संख्या ज्यादा है और सिर्फ 32 लाख लोगों को किट दी जाएगी। उसमें कितने लोगों को मिल पाती है यह देखने वाली बात होगी।

वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरने पर बैठे लालू-तेजस्वी

» नेता प्रतिपक्ष बोले-नागपुरिया कानून नहीं चलेगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम संगठनों के लोग गर्दनीबाग धरनास्थल पर प्रदर्शन कर रहे। इससे राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दिया।

इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे और मुस्लिम संगठन के नेताओं के धरने पर बैठ गए। इधर, तेजस्वी यादव ने मुस्लिम संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव आपके साथ खड़े होने के लिए धरनास्थल पर आए हैं। चाहे हमारी पार्टी सत्ता में हो या नहीं। हमलोग इस बिल के विरोध में रहेंगे। विपक्ष ने विधानसभा और विधान परिषद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। हमलोग इस बिल को गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक मानते हैं। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और उनकी पार्टी इस कानून को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

आप एक कदम उठाएंगे तो हम चार : तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने आज सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस बिल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सदन को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमलोगों किसी भी हाल में नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों के साथ मजबूती से खड़ा है और यदि वे एक कदम उठाएंगे, तो राजद के लोग चार कदम आगे बढ़ेंगे।

पिछड़ों के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों का रवैया द्वेषपूर्ण : मायावती

पार्टी की खुद संभाली कमान, युवा पीढ़ी को जोड़ने की तैयारी में बसपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लगातार कई चुनावों में हार से बेजार बसपा मुखिया मायावती ने अब खुद ही कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले बड़े-बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बसपा सुप्रीमों अब अपनी पार्टी की कीलकांटे को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। इसी के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। साथ ही, कई जिलों में भाईचारा कमेटियों का गठन भी किया है।

पार्टी कार्यालय में ओबीसी समाज की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दलितों की तरह ही पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों का जातिवादी, द्वेषपूर्ण व संकीर्ण रवैया रहा है। उनका शोषण और तिरस्कार हो रहा है। लिहाजा बहुजन समाज को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित करके व राजनीतिक शक्ति बनाकर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा।

गांव-गांव में जाकर बताएंगे भाजपा का छल

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भाजपा व सपा के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे के साथ-साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल तथा इन बहुजनों को उनके हक व न्याय से वंचित रखे जाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। हमेशा अलग-थलग व बिखरे ओबीसी समाज के लोगों को मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कराकर आरक्षण का संवैधानिक हक दिलाने से लेकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बसपा ने पार्टी व सरकार के स्तर पर जो ऐतिहासिक कार्य किए।

नई पीढ़ी को जोड़ने की कवायद

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में जिला स्तर पर विचार-संगोष्ठी के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग इस बार अपने पूरे परिवार के साथ खासकर युवा पीढ़ी को भी कार्यक्रम में लेकर आएं। सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि की जयंती व पुण्यतिथि के कार्यक्र म में भी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हों, जिससे युवा पीढ़ी अपनी पार्टी व मूवमेंट से अलग नहीं होगी। ऐसा करने से पार्टी को महिलाओं व युवाओं के लिए अलग से कोई फ्रंट आदि नहीं बनाने पड़ेंगे।

कई जिलाध्यक्ष भी बनाए गए

इसके अलावा पार्टी ने कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी घोषित किए हैं। अयोध्या मंडल के तहत अयोध्या में कृष्ण कुमार पासी, अंबेडकरनगर में सुनील सावंत गौतम, सुल्तानपुर में सुरेश कुमार गौतम, अमेठी में दिलीप कुमार कोरी, बाराबंकी में कृष्ण कुमार रावत, प्रयागराज में पंकज कुमार गौतम, महाकुंभ मेला में सतीश जाटव, फतेहपुर में डॉ. दीप गौतम, प्रतापगढ़ में सुशील कुमार गौतम, कौशांबी में राकेश कुमार गौतम, मिर्जापुर में राजकुमार भारती, सोनभद्र में रामचंद्र रवा, भदोही में शिवनारायण गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

मैंने कभी संविधान बदलने की बात कही हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं: डीके शिवकुमार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर यह आरोप सही साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। उपमुख्यमंत्री ने भाजपा पर उनके राजनीतिक रुख को बर्दाश्त न कर पाने के कारण 'झूठे दावे प्रसारित' करने का आरोप लगाया।

शिवकुमार ने यह भी बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उनकी टिप्पणियों के बारे में पूछताछ की थी और एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में दिए गए बयान के वीडियो की समीक्षा करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। शिवकुमार ने सार्वजनिक अनुंबधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया था। एक सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा, '' क्या मैं पागल हूं। इस मुद्दे को उठाने वाले पागल हो गए हैं। भाजपा नेता मेरे साक्षात्कार में कही गई बातों को स्वीकार नहीं कर सकते, न ही वे मेरे राजनीतिक रुख को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने संविधान बदलने के बारे में कहां कहा है। यह तो उनकी पार्टी के सदस्य ही हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है।' पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''अगर मैंने कभी संविधान बदलने की बात कही तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। क्या वे (भाजपा) इस चुनौती को स्वीकार करेंगे।

संविधान-कानून की अनदेखी कर रही भजनलाल सरकार : डोटासरा

» कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- राजस्थान में कानून खत्म

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार न तो संविधान को मान रही है और न ही कानून को। नगर निगम और नगर निकायों में चुने गए जनप्रतिनिधियों के चुनाव अब तक नहीं कराए गए हैं। वन स्टेट, वन इलेक्शन के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि विकास कार्यों में सरकार रुकावट डाल रही है।

डोटासरा ने कहा कि सरकार बिना जांच के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटा रही है। यहां तक कि कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद भी उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया।डोटासरा ने कहा कि सरकार जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर प्रशासक लगा रही है, जबकि ऐसा करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयोग निष्क्रिय पड़ा है और इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। डोटासरा ने ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) में हो रही बैठकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी कानूनी अधिकार के पार्टी स्तर पर कमेटियां बनाकर सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी और अरुण चतुर्वेदी जैसी बीजेपी के नेता बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं।

चुनाव न कराने पर सरकार पर निशाना

डोटासरा ने श्रीगंगानगर के दो वार्डों में चुनाव नहीं कराने का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में भी चुनाव न होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

'महाकुंभ हादसे के शिकार परिवारों के साथ धोखा'

» पीसीसी अध्यक्ष अजय राय का दावा- मुआवजा 25 की जगह पांच लाख दिया गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने दावा किया कि प्रयागराज हादसे में दम तोड़ने वाले लोगों के परिजनों को पुलिस द्वारा 25 की जगह पांच-पांच हजार रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अभी तक मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्या भाजपा सरकार मुआवजे के नाम पर नया घोटाला करने की तैयारी में है? इस दौरान उन्होंने झारखंड में मुआवजा देने गई उत्तर प्रदेश पुलिस की तस्वीर भी सार्वजनिक की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि बदहाली और अव्यवस्था का शिकार हुए कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे में तमाम लोगों की मौत हुई। पहले तो सरकार ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो 30 लोगों की मौत को भाजपा सरकार ने स्वीकार किया। जबकि कांग्रेस की ओर से लगातार यह गया जाता रहा कि अलग-अलग राज्यों के तमाम लोगों की मौत हुई है। सरकार अपने तंत्र के जरिए इनकी खोज कराए और सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे। अब भाजपा सरकार की हकीकत सामने आ रही है। झारखंड का प्रकरण तो एक सबूत मात्र हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं।

उन्होंने कुछ तस्वीरें, अखबार में छपी खबरों को दिखाते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार अपने झूठ को छुपाने के लिए नियम विरुद्ध रास्ते अपनाकर मृतकों के आश्रितों को चुप कराने की कोशिश कर रही है।

सरकार व पुलिस करतूतों पर डाल रही है पर्दा

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए बगैर उत्तर प्रदेश पुलिस मृतकों के परिजनों को नगद रुपये दे रही है। इसके जरिए अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री अजय राय ने दावा किया कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के सुंदर नगर के रहने वाले शिवराज गुप्ता की प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मृत्यू हुई थी। उनका नाम मृतकों की सूची में नहीं था। ना ही प्रदेश सरकार ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस उनके आवास पर पहुंची और आश्रितों को पांच लाख रुपये का नकद मुआवजा दी। जब शिवराज गुप्ता के पुत्र शिवम ने पांच लाख रुपये लेने से इनकार कर दिया। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा 25 लाख रुपये घोषित किया था। नकदी में बिना कागजी प्रक्रिया पूरी किए यह मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? जबकि झारखण्ड के स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसी किसी भी कार्यवाही से अनभिज्ञता जताई है।

पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में भी दिए पांच- पांच लाख

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि उनके पास ऐसी भी जानकारी आई है कि पश्चिम बंगाल के भी दो परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये नकद दिए गए हैं। वहां भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जताई गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही छुपा कर क्यों की जा रही है? घटना को लगभग 2 महीने के करीब बीत चुके हैं। मगर अभी तक ना मृतकों की सही सूची और ना ही लापता की सूची जारी नहीं की गई है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के दिल्ली स्थित आवास पर एसआईटी ने भेजा नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार दोपहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शाही जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की एक दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें वे धाराएं भी शामिल हैं जिनके तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। संभल में पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई हिंसा के मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान वर्क को पूछताछ के लिए नोटिस तामील कराने पहुंची, लेकिन वह और उनके परिवार का कोई नहीं मिला।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।इस बीच, देर शाम बर्क के निजी सहायक अब्दुल रहमान ने फोन पर बताया, ''हमें सांसद के (दिल्ली स्थित) आवास पर नोटिस मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें नोटिस दिया है। इसके पहले, संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सांसद के निवास पर एसआईटी नोटिस तामील कराने गयी थी, लेकिन वह नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि अब एसआईटी की टीम उनको नोटिस तामील कराने दिल्ली जाएगी। सोमवार को विश्नोई ने पत्रकारों को बताया था कि 24 नवंबर की हिंसा के संबंध में दर्ज मामले में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

नहीं थम रहा महाराष्ट्र में विवादों का सिलसिला !

डिप्टी सीएम शिंदे पर वायरल कविता को लेकर वार-पलटवार

» सियासी उठापटक के बाद अब सामाजिक रार शुरू

» भाजपा-शिवेसना व शिवेसना यूबीटी में रार

» कॉमंडियर कामरा के खिलाफ शिवसैनिकों में आक्रोश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र में विवाद रूकने के नाम नहीं ले रहें हैं। कभी सरकार गठन को लेकर किचकिच होती है तो कभी भाजपा, शिवेसना व राक्रंपा के बीच मतभेद को लेकर चर्चा आम हुई रहती है। अब वहां नया बवाल हो गया है है। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी कविता में उपमुख्यमंत्री शिंदे को गद्दार बताया था। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद से महायुति सरकार से लेकर शिवसेना व भाजपा तक के निशाने पर वह आ गए हैं। जहां राज्य के सीएम फडणवीस ने कामरा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है तो उपमुख्यमंत्री शिंदे ने व्यंग के आधार पर सीमा लांघना ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कामरा का समर्थन किया है।

उधर इन सबके बीच कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रविवार को शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर 'गद्दार' वाला मजाक बनाकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। किसी का नाम लिए बिना कामरा ने हिंदी फ़िल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने में बदलाव करके शिंदे का मज़ाक उड़ाया था। शिवसेना नेताओं ने कामरा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की थी और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कामरा से उनकी निम्न स्तरीय कॉमेडीके लिए माफी मांगने का आग्रह किया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मुंबई के खार इलाके में स्थित 'हैबिटेट स्टूडियो' में कथित रूप से तोड़फोड़ करने को लेकर शिवसेना के करीब 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई में खार क्षेत्र स्थित 'हैबिटेट कॉमेडी क्लब' में कथित रूप से तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा का कार्यक्रम शूट किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिंदे पर ''गद्दार'' शब्द के जरिये कटाक्ष किया था। कामरा ने फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने के संशोधित संस्करण का इस्तेमाल करके शिंदे पर कटाक्ष किया था। राउत ने कहा कि कामरा ने अपने व्यंग्यात्मक गीत में किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा, ''यह घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि फडणवीस गृह विभाग को संभालने में अक्षम हैं।''

व्यंग्य की भी एक सीमा होनी चाहिए : शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा द्वारा उनके खिलाफ कथित मजाक को लेकर उठे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एकनाथ शिंदे ने विवाद के बीच में कहा है कि हम व्यंग्य समझते हैं, लेकिन इसकी भी सीमा होनी इस विवाद पर अपने पहले बयान में शिंदे ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम व्यंग्य को समझते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा, विपक्ष पर स्पष्ट कटाक्ष करते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि कॉमेडियन का उन पर कथित मजाक किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। गौरतलब है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा का शो आयोजित किया गया था। कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुंबई पुलिस ने पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया और गिरफ्तार भी किया शिवसैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिंदे ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।

कॉमेडियन कुणाल कामरा को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से माफी मांगना चाहिए : फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई अपमाजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि ऐसे निंदनीय कृत्यों का समर्थन करने वाले अर्बन नक्सलियों और वामपंथी उदारवादियों को सबक सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान शिंदे के खिलाफ कामरा की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच आया है। उन्होंने राज्य विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कामरा का यह कृत्य निंदनीय है।

शिवसेना नेता राहुल कनाल ने कॉमेडियन को धमकी दी

मुंबई पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी राहुल कनाल और उनके 11 साथियों को मुंबई के एक होटल परिसर में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस होटल परिसर में ही स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादास्पद देशद्रोही टिप्पणी की थी। हालाँकि, स्थानीय अदालत ने उन्हें उसी दिन

जमानत दे दी। खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने प्रदर्शन के दौरान कुणाल कामरा ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था और उनकी पैरोडी भी गाई थी। टिप्पणी से गुस्साए राहुल कनाल के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को कुणाल कामरा के शो स्थल पर तोड़फोड़ की। खार पुलिस ने घटना के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में 19 लोगों की पहचान की है और उनके नाम दर्ज किए हैं। साथ ही, आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ करने वाले 15 से 20 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने सोमवार को शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े राहुल कनाल सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें बांद्रा में मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया।

आत्मसम्मान की बात आएगी तो होगा बवाल : कनाल

कनाल के हवाले से कहा, यह कानून को अपने हाथ में लेने की बात नहीं है। यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है। जब बात बुजुर्गों या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है... जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे... संदेश (कुणाल कामरा के लिए) स्पष्ट है, अभी तक तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप मुंबई में होंगे, आपको शिवसेना शैली में एक अच्छा सबक मिलेगा।अपने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कनाल ने कहा कि वे कुणाल कामरा को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा, हमने शिकायत की थी, हमने मालिक (हैबिटेट सेट के) को भी बुलाया था और उन्हें बताया था कि इस जगह के खिलाफ पहले भी 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं... कुणाल कामरा के लिए हमारा संदेश है कि हम उन्हें उनके किए के लिए सबक सिखाएंगे, लेकिन यह एक सोची-समझी साजिश है और मुंबई पुलिस इसका पर्दाफाश करने में सक्षम है।खार पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विजय के अनुसार, शिंदे सेना का युवा गुट उस समय कार्यक्रम स्थल में घुस आया जब स्टैंडअप कॉमेडियन रजत सूद का लाइव शो चल रहा था और उन्होंने शो को बंद करवा दिया तथा सेट पर तोड़फोड़ की।

माफी नहीं मांगूंगा : कुणाल कामरा

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पुलिस से कहा है कि वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने कथित कटाक्ष के लिए माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कानून का पालन करेंगे। सूत्रों के अनुसार, कामरा ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल वह मुंबई में नहीं हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने अभी तक कुणाल कामरा को उनके सामने पेश होने के लिए कोई तारीख नहीं दी है। स्टैंड-अप कॉमेडियन ने पूर्ववर्ती शिवसेना से अलग होकर भाजपा में शामिल होने के लिए शिंदे पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। उनकी टिप्पणी के बाद, राजनीतिक संगठन ने उन्हें धमकियों और पुलिस शिकायत के माध्यम से निशाना बनाया।

गद्दारों को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं : उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने सोमवार को मांग की कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उस स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं से नुकसान की भरपाई करनी चाहिए जहां 'स्टैंड-अप कॉमेडियन' कुणाल कामरा का शो शूट हुआ थाकुणाल कामरा विवाद और शिवसेना (शिंदे गुट) कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ ग़लत कहा है। उन्होंने कहा कि गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है। पूरा गाना (कुणाल कामरा के शो का) सुनें और दूसरों को भी सुनाएँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना का इस हमले से कोई लेना-देना नहीं है, यह

गद्दार सेना ने किया है। जिनके खून में गद्दारी है वे कभी शिवसैनिक नहीं हो सकते।उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने मांग की कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उस स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं से नुकसान की भरपाई करनी चाहिए जहां 'स्टैंड-अप कॉमेडियन' कुणाल कामरा का शो शूट हुआ था। राउत ने पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य की राजधानी में ''गुंडा राज'' है। उन्होंने कहा कि फडणवीस गृह विभाग को संभालने में अक्षम हैं। मुंबई पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर 'स्टैंड-अप कॉमेडियन' कुणाल कामरा के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

साइबर ठगों के हौसलों को पस्त करना जरूरी

पिछले कुछ सालों से साईबर ठगी की खबरें आम हो गई हैं। अब साइबर ठगों ने एआई का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आए दिन डिजिटल अरेस्ट द्वारा कई लोगों के शिकार होने की बातें सामने आती है। जब घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो सरकारें या संबंधित एजेंसियां जनता की जागरूकता से जुड़े कुछ स्लोगन या विज्ञापन जारी करके अपने कर्तव्यों की इतीश्री कर लेती हैं। जबकि ये मामले बहुत गंभीर होते जा रहे हैं अब नीति नियंताओं को इसपर गंभीरता से विचार करके कानून बनाना चाहिए। वर्तमान समय में ये ठग एआई का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। अब समय आ गया है कुछ ठोस किया जाए। ऐसा नहीं है कि साइबर या इससे जुड़ी ठगी हमारे यहां ही होती है अपितु देखा जाए तो यह आयातित ठगी का तरीका है। साइबर या यों कहें कि इस तरह की ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान पर है तो यूक्रेन दूसरे पायदान पर बना हुआ है।मोबाइल पर नंबर मिलाते ही आजकल साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन या ब्लेक मेलिंग से सतर्क रहने का संदेश सुनने को मिलता है। इस सबके बावजूद भारत सरकार द्वारा ठगी के जारी आंकड़ें ना केवल चेताने वाले हैं अपितु लगता है जैसे ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाले हालात बनते जा रहे हैं।

मजे की बात यह है कि साइबर ठगी के इन रुपों से सबसे अधिक शिकार पढ़े लिखे और समझदार लोग ही हो रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों को देखे तो पिछले तीन साल में ही ठगी के नए अवतार से ठगी की राशि 20 गुणा बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत के दो महीनों में ही 17 हजार 718 से अधिक मामलें दर्ज हो चुके हैं और 210 करोड़ 21 लाख रु. से अधिक की ठगी हो चुकी है। यह तो साल की शुरुआत के हाल है। पिछले तीन साल के आंकड़ों पर नजर ड़ाले तो हालात की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। साल 2022 में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की ब्लेक मेलिंग, ऑनलाइन ठगी आदि के 39925 मामलों में 91 करोड़ 14 लाख की ठगी हुई थी जो एक साल बाद ही 2023 में बढ़कर 60676 हो गई और इसमें 339 करोड़ रु. की राशि की ठगी हो गई। मजे की बात यह है कि लाख प्रयासों के बावजूद 2024 की बढ़ोतरी तो और भी चिंतनीय रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 2024 में एक लाख 23 हजार 672 मामलें दर्ज हुए और 1935 करोड़ 51 लाख रु. की ठगी हो गई। यह तो वे मामलें हैं जो पुलिस में दर्ज हुए हैं जबकि हजारों मामलें ऐसे भी होंगे जिनमें मामलें दर्ज कराए ही नहीं गए होंगे। खास बात यह है कि ठगी के केन्द्र व ठगी के तरीके से वाकिफ होने के बावजूद यह होता जा रहा है। हांलाकि झारखण्ड के जमातड़ा से ठगों के तंत्र को तोड़ दिया गया पर देश में एक दो नहीं अपितु 74 जिलों में इस तरह की ठगी करने वालों के हॉटस्पॉट विकसित हो गए। झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के केन्द्र पहले पांच प्रमुख सेंटर विकसित हो गए। लोगों में जागरूकता के साथ ही इनसे निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।

“ वर्तमान समय में ये ठग एआई का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। अब समय आ गया है कुछ ठोस किया जाए। ऐसा नहीं है कि साइबर या इससे जुड़ी ठगी हमारे यहां ही होती है अपितु देखा जाए तो यह आयातित ठगी का तरीका है। साइबर या यों कहें कि इस तरह की ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान पर है तो यूक्रेन दूसरे पायदान पर बना हुआ है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

वित्तीय अनुशासन से खुलेगी विकास की राह

के.एस. तोमर

एक लाख करोड़ से अधिक के कर्ज़ के बोझ तले दबे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उम्मीदों के सहारे केंद्र सरकार से राज्य के लोगों के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहे हैं। मकसद है इस गंभीर वित्तीय संकट से प्रदेश को उबारा जा सके। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी केंद्र सरकार से पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान करने की मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व स्रोतों के कारण राज्य को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त विभाग संभाल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन और महत्वाकांक्षी विकास पहलों के बीच संतुलन साधना है। बजट का फोकस पर्यटन विस्तार, हरित ऊर्जा संवर्धन और ग्रामीण सशक्तीकरण पर है, जो आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक माने जा रहे हैं।

हालांकि, राज्य वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें केंद्रीय अनुदानों में गिरावट, बढ़ता कर्ज और राजस्व व्यय में वृद्धि जैसी समस्याएं शामिल हैं, जो वित्तीय योजना के लिए बड़ी बाधाएं हैं। आर्थिक दबावों के बावजूद, सुक्खू ने दीर्घकालिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है और बाहरी उधारी पर निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना शामिल है। हालांकि, सीमित राजस्व स्रोतों और ब्याज भुगतान के बढ़ते बोझ के कारण सरकार के लिए विकासोन्मुख और वित्तीय रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण बनाए रखना कठिन चुनौती है। बजट में वैकल्पिक राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए उच्च कर संग्रह, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और राज्य संसाधनों का कुशल उपयोग शामिल है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या ये उपाय वित्तीय घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त होंगे, बिना विकास लक्ष्यों को प्रभावित किए।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति कई संरचनात्मक और नीतिगत कारणों से प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय अनुदानों में तेज गिरावट रही है। विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान, जो 2021-22 में रु. 10,949 करोड़ था वह 2025-26 में घटकर रु. 3,257 करोड़ रह गया है। इसके अलावा, जीएसटी मुआवजा बंद होने से

रु. 9,478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, जिससे वित्तीय असंतुलन और बढ़ गया है। राज्य का कुल कर्ज रु. 1,04,729 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें से रु. 29,046 करोड़ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उधार लिया गया है। राज्य को पूंजीगत व्यय में 46.58 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। इससे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में निवेश की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। राजस्व घाटा रु. 361 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.83 प्रतिशत है। वहीं, कुल राजस्व घाटा रु. 96 करोड़ की मामूली गिरावट के साथ रु. 6,486 करोड़ से रु. 6,390 करोड़ हो गया है, जो जीएसडीपी का 1.43 प्रतिशत है। वित्तीय घाटा रु. 10,338 करोड़ बना हुआ है, जो राज्य के जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद वित्तीय दबाव बना हुआ है। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा नशीली दवाओं पर अंकुश को एसटीएफ का गठन किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (2025) माफिया गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। बजट में पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 500 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और शिमला रोपवे प्रोजेक्ट का काम 2025-26 में शुरू करने की योजना शामिल है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 70-75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों की बकाया पेंशन मई तक चुकाने का प्रस्ताव है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के रु. 10,000 करोड़ के बकाया एरियर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

शिक्षा प्रशासन के पुनर्गठन के तहत स्कूलों और कॉलेजों के लिए अलग-अलग निदेशालय बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का 2025-26 बजट में वेतन और पेंशन पर कुल व्यय का 45 प्रतिशत है। विकास कार्यों के लिए 24 प्रतिशत और ब्याज भुगतान व कर्ज की अदायगी में 22 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। राजस्व वृद्धि के लिए राज्य को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। राज्य संपत्तियों का मौद्रीकरण, प्रदेश को पारिस्थितिक योगदान के लिए वित्तीय मान्यता दिलाना, इको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा परियोजनाओं से निजी निवेश आकर्षित करना, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

विश्वसनीय बनाएं सामुदायिक सेवा की सजा को

के.पी. सिंह

माह जनवरी 2025 में, जम्मू में तीसरे अतिरिक्त दण्डाधीश के न्यायालय ने एक व्यक्ति को यातायात में बाधा डालने और सार्वजनिक स्थल पर हल्ला-गुल्ला करने का दोषी पाते हुए एक सप्ताह की सामुदायिक-सेवा करने की सज़ा सुनाई। उसे डैन्सल में एक स्वास्थ्य केन्द्र में सफाई करने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में, इसी अदालत ने एक अन्य दोषी को एक सप्ताह तक प्रतिदिन तीन घंटे के लिए झंज्जर कोटली में एक सार्वजनिक पार्क को साफ करने का आदेश दिया। दोनों मामलों में पुलिस थाना प्रभारी को अनुपालना सुनिश्चित करवाने और फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। इसी माह, ऐसे ही तीसरे मामले में कटरा की एक उप-न्यायाधीश अदालत ने अपराधी को लगातार तीन दिनों तक एक पार्क की सफाई और रख-रखाव करके सामुदायिक-सेवा का प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। कटरा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। 6 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट चण्डीगढ ने एक यातायात उल्लंघनकर्ता को प्रवर पुलिस अधीक्षक (यातायात) के रीडर की देखरेख में पांच दिनों तक सामुदायिक-सेवा करने के आदेश दिए हैं। च्सामुदायिक-सेवाज् को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 4 के अन्तर्गत सज़ा की सूची में पहली बार जोड़ा गया है। छह प्रकार के अपराधों में लोक सेवकों के द्वारा व्यापार (धारा 202), सार्वजनिक-सेवा करने की सज़ा प्रस्तावित है। कदाचार (303(2), नशे में गाड़ी चलाना (धारा 355) और मानहानि (धारा 356 (2), जैसे जुर्म शामिल हैं। सज़ा के तौर पर सामुदायिक-सेवा को शामिल करना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में चुन:स्थापनात्मक न्यायज् की अवधारणा के दर्शन होते हैं, जिसमें अपराधियों को बिना हिरासत में लिए सुधारात्मक उपायों का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है।

च्सामुदायिक-सेवाज् शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 23 में एक स्पष्टीकरण के रूप में जोड़कर परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है च्सामुदायिक सेवाज् का अर्थ उस काम से होगा जो अदालत एक सजा के रूप में निर्धारित कर सकती है। जिसके लिए दोषी को कोई पगार नहीं दी जाएगी। बिना पगार के काम करवाना संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा प्रतिबन्धित है। यह देखना रोचक होगा कि फिर किस प्रकार बिना वेतन के सामुदायिक सेवा करने के आदेश को उचित ठहराया जा सकता है। सामुदायिक-सेवा की परिभाषा में शब्द च्काम जो अदालत आदेश दे सकती हैज् और च्जो समाज को लाभान्वित करता होज् अस्पष्ट है और अनिश्चितताओं से भरे हैं, क्योंकि सुनवाई करने वाली अदालत की कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया गया है। जीवन की घटनाओं के बारे में प्रत्येक इंसान की व्यक्तिगत धारणाएं होती हैं, अत: सामुदायिक-सेवा के लिए उपयुक्त कार्य देने हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए उचित कार्य न ढूंढ़ पाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। उच्च न्यायालय के च्नियमों और आदेशोंज् में इस प्रकार के कार्यों की एक विचारोत्तेजक सूची के रूप में शामिल करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सामुदायिक-सेवा की सज़ा की निगरानी, पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग के लिए निष्पादन एजेंसी को नामित करने के बारे में भ्रम प्रचलित है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों को अदालतों द्वारा यह कार्य दिया जा रहा है, बिना इस बात को महसूस किए कि ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, और न ही वे ऐसे दोषियों को सम्भालने के लिए पर्याप्त कौशल रखते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमों/दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति में, वे इस तरह के महत्वपूर्ण कर्तव्य को करने के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण के बारे में भी पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। यह याद रखना चाहिए कि सामुदायिक-सेवा बीएनएस के अन्तर्गत एक सम्पूर्ण सज़ा है जिसके निष्पादन के लिए पूर्णरूप से आपराधिक न्याय प्रणाली की एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं। सरकार के च्यवसाय के नियमोंज् में च्कानून और न्यायज् गृह मंत्रालय के विषय के रूप में सूचीबद्ध किए गए है। गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी एजेंसी को सामुदायिक-सेवा की सज़ा को निष्पादित करने के लिए कर्तव्य सौंपना एक बड़ी प्रशासनिक भूल होगी। यह वांछनीय है कि सामुदायिक-सेवा को गृह विभाग के कर्तव्यों की सूची में शामिल किया जाए और इसके निष्पादन के लिए आवश्यक तौर-तरीके निर्धारित किए जाए।

आपराधिक मामलों में सज़ा का निष्पादन करना जेल विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसके लिए नियम और प्रक्रियाएं राज्यों के च्जेल मैनुअलज् में निर्धारित हैं। चूंकि, सामुदायिक-सेवा की सज़ा वर्तमान में ही बीएनएस में शामिल की गई है, अत: जेल के नियमों और विनियमों में इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए, कुछ जेल प्रशासक और मैजिस्ट्रेट अक्सर सामुदायिक-सेवा की सज़ा पाए दोषियों और परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों में अन्तर करने में चूक जाते हैं। परिवीक्षा पर अपराधी को छोड़ना एक सज़ा नहीं है। यह सजा-पूर्व का सुधारात्मक आदेश है जिसमें पहली बार अपराध करने वाले अपराधी को पर्यवेक्षण में छोड़कर सुधरने का एक मौका दिया जाता है। इसे च्रुका हुआ फैसलाज् कह देना ज्यादा उचित होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस और जेल विभाग अपराध और आपराधिक सज़ा के सभी रिकार्ड का भण्डार है। यदि किसी दोषी को सामुदायिक-सेवा करने की सज़ा दी जाती है।

जोड़ों के दर्द में राहत

जोड़ों के दर्द के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला तरल पदार्थ जिसे बोन मैरो कहते हैं। हड्डियों के बीच बोन मैरो में कमी आ जाती है जिससे जोड़ों के बीच हड्डियां आपस में टकराने लगती है और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे होने वाला दर्द काफी दर्दनाक होता है। जब भी आपको जोड़ों का दर्द हो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे सूजन और दर्द से आराम मिलेगा। कच्ची हल्दी में कुरकुमिन नामक यौगिक होता है जो जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने में मदद करता है। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और कई जगह दिखाने के बावजूद आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप कच्ची हल्दी का सेवन करना शुरू कर दें। कच्ची हल्दी आपको जोड़ों के दर्द से काफी निजात दिलाती है। रोजाना रात को आप कच्ची हल्दी को दूध में डालकर उबाल लें। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने पर पीएं। इसके अलावा हल्दी के प्रयोग से आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। घुटनों में दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए आप हल्दी वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।

किसी अमृत से कम नहीं है कच्ची हल्दी

किचन में हल्दी एक ऐसी चीज है जो काफी गुणकारी होती है। चाहे आप हल्दी को आप मसाले के तौर पर इस्तेमाल करें, पान में घोलकर पीएं या शहद में डालकर खाएं। हल्दी के कई फायदे हैं। यह आपकी सेहत के लिए काफी रामबाण है। कच्ची हल्दी का उपयोग आयुर्वेद में कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। खाना बनाने के साथ ही, इसका इस्तेमाल औषधीय और ब्यूटी को निखारने के लिए वर्षों से किया जा रहा है। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी कम्पाउंड्स होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इसे लगाने से मुरझाई त्वचा में जान आ जाती है। फोड़े-फुंसियों से छुटकारा मिल सकता है। त्वचा पर ग्लो आता है। आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में हल्दी को शामिल कर सकते हैं। इसके अधिक लाभ पाने के लिए आप हल्दी में शहद, दही, दूध आदि मिलाकर लगाएं तो कई तरह से फायदेमंद होगा।

कैंसर में राहत

वहीं कच्ची हल्दी में कुरकुमिन नामक यौगिक होता है जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। कच्ची हल्दी का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है, खासकर यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं या किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। हल्दी कई रूपों में पाई जा सकती है- पाउडर, चाय, अर्क, कैप्सूल और कटी हुई जड़ या सप्लीमेंट। कई मामलों में, कैंसर के इलाज के दौरान साबुत हल्दी - हल्दी की जड़ या पाउडर - की सलाह दी जाती है।

स्किन एलर्जी से बचाए

कच्ची हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफलेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की समस्याओं में राहत दिलाने में मदद करते हैं। दूध के अलावा भी आप कच्ची हल्दी को पानी में उबाल लें। फिर इस पानी को आप गर्म पानी की बोतल में मिला लें। पूरे दिन अब आप इस पानी को पीते रहें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के लिए काफी लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही यह पेट की समस्याओं को भी दूर करती है।

पाचन तंत्र करे मजबूत

खराब डाइट और बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से गैस, एसिडिटी और अपच की परेशानी आम होती जा रही है। पाचन से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं और कई तरह की दवाईयों का सेवन करते हैं फिर भी उनकी समस्याओं का उपचार नहीं होता। गैस, अपच, अल्सर और आंतों की सूजन पेट से जुड़ी ऐसी परेशानियां है तो आप कच्ची हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर मोड पर कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में काफी गुणकारी है। वहीं कच्ची हल्दी में विटामिन सी और ई होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आंत की सेहत को दुरुस्त रखने में हल्दी का सेवन बेहद असरदार साबित होता है। हल्दी का सेवन करने से पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं जिसका सेवन करने से गैस, अपच, अल्सर का उपचार होता है।

हंसना मना है

एक लड़की- हे भगवान, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो, भगवान - घर जाओ बेटी समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते!

संता- आज तेरे मोबाइल पे बड़े मैसेज आ रहे है, क्या बात है? बंता- ओ कुछ नही यार, अपनी ऐसी किस्मत कहां, आज तो बीवी का मोबाइल लाया हूं!

एक लड़का फेल हुआ तो उसके पापा ने कहा, देख- देख उस लड़की को देख, वो तुम्हारे साथ पढ़ती है और 1st आयी है। लड़का- देख देख क्या देख, उसी को देख-देख के तो फेल हुआ हूं!

लड़की- अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का- मैं भी मर जाऊंगा, लड़की - पर क्यों? लड़का- कभी-कभी ज्यादा खुशी भी जान ले लेती है!

पिताजी - बेटा, मेरे लिए 1 ग्लास पानी लाना, लड़का - नहीं लाऊंगा, दूसरा लड़का - रहने दो पापा, ये तो है ही बत्तमीज, आप खुद लेलो, और मेरे लिए भी 1 ग्लास ले आना!

एक बुजुर्ग व्यक्ति- बेटा कैसे हो, बच्चा- ठीक हूं, बुजुर्ग- पढ़ाई कैसी चल रही है?, बच्चा - बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह.! बुजुर्ग-मतलब? बच्चा- भगवान भरोसे.!

कहानी — राजा और मूर्ख बंदर

बहुत पुरानी बात है, एक राजा के पास पालतु बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था। उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झल रहा था, तभी एक मक्खी भिन भिनाते हुए राज के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार-बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफी समय तक ऐसे ही मक्खी को भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है, तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देख कर राजा काफी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है, तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलता है। इसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है, तो बंदर के तलवार से राजा के बाल कट जाते है और जब मूंछ पर बैठती है, तो मूंछ कट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल-पुथल मच जाती है।

कहानी से सीख-इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी मूर्ख को ऐसा काम न सौंपे, जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दें।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों से संबंध सुधरेंगे।

वृषभ

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग परेशानी का कारण रह सकता है। दूसरों के कार्य में दखल न दें। बड़ों की सलाह मानें। लाभ होगा।

मिथुन

प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बेवजह कहासुनी हो सकती है। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

कर्क

किसी अपने के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु पस्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें।

सिंह

घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा।

कन्या

शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है।

तुला

शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधन जुटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। लंब समय से रुके कार्य सहज रूप से पूर्ण होंगे। कार्य की प्रशंसा होगी।

वृश्चिक

घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अज्ञात भय रहेगा।

धनु

आंखों का ख्याल रखें। अज्ञात भय सताएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। कानूनी अड़चन आ सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

मकर

स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। किसी अपरिचित पर अतिविश्वास न करें। विवाद से क्लेश होगा। दूसरों के उकसाने में न आएं। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।

कुम्भ

शारीरिक कष्ट संभव है तथा तनाव रहेंगे। सुख के साधन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी।

मीन

चोट व रोग से परेशानी संभव है। आराम तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। यश बढ़ेगा। व्यापार वृद्धि होगी। नई योजना बनेगी जिसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा।

'छोरी 2' का टीजर रिलीज, खौफनाक मंजर में दिखीं नुसरत भरुचा और सारा

साल 2021 में फिल्म 'छोरी' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इसमें एक सामाजिक कुरीति को भूतों की कहानी के साथ जोड़कर दिखाया गया था। अब इस फिल्म का अगला पार्ट यानी 'छोरी 2' भी ओटीटी पर रिलीज होने वाला है। इस फिल्म के हालिया रिलीज टीजर में अभिनेत्री नुसरत भरुचा नजर आ रही हैं। वह पहली फिल्म का भी हिस्सा थीं। 'छोरी 2' के टीजर में भी पिछली फिल्म की तरह की हॉरर, ड्रामा नजर आ रहा है।

फिल्म 'छोरी 2' के टीजर को प्राइमवीडियोइन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी साझा किया है। इसके साथ ही एक कैप्शन भी लिखा है, 'एक बार फिर, वो खेत, वो खतरा और वो खौफ'। टीजर में भी यही सब बातें नजर आती हैं। नुसरत भरुचा का किरदार अपने आपको एक खेत में खौफनाक परिस्थितियों में घिरा हुआ पाता है। टीजर में छोटी-छोटी लड़कियां भी नजर आती हैं, साथ ही भूत भी नजर आते हैं। डरावना म्यूजिक टीजर में कहानी को और प्रभावित बना रहा है।

फिल्म 'छोरी 2' में नुसरत भरुचा के अलावा सोहा अली खान, सौरभ गोयल, पल्लवी अजय, कुलदीप सरीन, हार्दिक शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म को विशाल फुरिया और अजीत जगतप ने लिखा है। निर्देशन की जिम्मेदारी विशाल फुरिया निभा रहे हैं। फिल्म 'छोरी 2' के प्रोडक्शन से एबंडेशिया एंटरटेनमेंट भी जुड़ा है। इस प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म 'छोरी 2' बनाने का मकसद साझा किया है। वह कहते हैं, 'पहली फिल्म 'छोरी' को जो प्यार दर्शकों ने दिया, उसे देखते हुए 'छोरी 2' बनाने का फैसला लिया गया है। इस बार फिल्म में हॉरर की डोज को बढ़ा दिया गया है।

साध्वियों से मिलीं तमन्ना भाटिया ओडेला 2 के लिए लिया आशीर्वाद

तमन्ना भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह कुछ साध्वियों के बीच बैठी दिख रही हैं। साध्वियों और अभिनेत्री के बीच आध्यात्मिक संवाद हो रहा है। तमन्ना के चेहरे पर भी शांति और प्रसन्नता नजर आ रही है। यह कार्यक्रम तमन्ना की आने वाली फिल्म 'ओडेला 2' से जुड़ा है।

तमन्ना भाटिया ने जो वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है, उसमें वह कुछ साध्वियों से आशीर्वाद ले रही हैं। इन साध्वियों का पहनावा, वेश-भूषा बिल्कुल वैसी ही है, जैसी फिल्म 'ओडेला 2' में तमन्ना भाटिया के किरदार की है। ये साध्वियां असल में भगवान शिव की स्तुति करती हैं, उनके लिए ही समर्पित रहती हैं। इन साध्वियों से तमन्ना ने बहुत देर तक बातचीत की।

फिल्म 'ओडेला 2' की कहानी की बात की जाए तो यह एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को अशोक तेजा ने निर्देशित किया है। फिल्म में तमन्ना भाटिया का किरदार काफी चुनौतीपूर्ण है। ट्रेलर में तो अभिनेत्री का रूप काफी रौद्र नजर आया था। यह फिल्म 'ओडेला रेलवे स्टेशन' की अगली कड़ी है।

अगर तमन्ना भाटिया के निजी जीवन की बात करें तो प्रेमी विजय वर्मा ने उनका अलगाव हो चुका है। इनकी राहें अब जुदा हो चुकी हैं। दोनों को लंबे वक्त से साथ नहीं देखा गया है। इन्हीं खबरों के बीच ही तमन्ना भाटिया अपनी आने वाली फिल्म 'ओडेला 2' का प्रचार कर रही हैं।

बॉलीवुड | **मन की बात**

केवल दो मिनट की लोकप्रियता के लिए लोग करते हैं कमेंट : कंगना

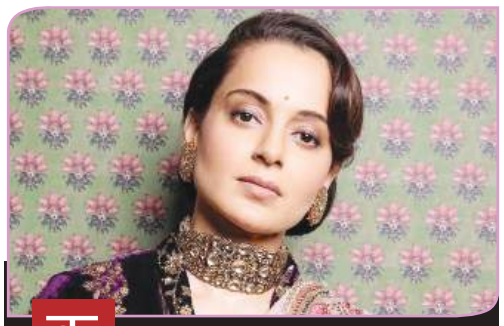

कुणाल कामरा पर विवाद गरमाया हुआ है। जबसे उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कमेंट किया है वो मुश्किल में फंसे हैं। कुणाल ने कॉमेडी एक्ट में एकनाथ शिंदे की राजनीति पर तंज कसते हुए उन्हें गद्दार बताया था। शिंदे गुट के नेता कुणाल पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर मंडी की सांसद कंगना रनौत का रिएक्शन आया है। एक्ट्रेस ने कुणाल के कॉमेडी एक्ट की निंदा की है। वो कहती हैं- आप कोई भी हो, किसी का अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना सही नहीं है। जिस इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। उनके काम की बेइज्जती कर रहे हैं। शिंदे जी एक जमाने में रिक्शा चलाया करते थे। आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। इनकी खुद की क्या योग्यता है? कौन हैं ये लोग? जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए। अगर लिख सकते तो साहित्य में लिखते कॉमेडी हो या कुछ भी। कॉमेडी के नाम पर गालीगलौच करना, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना...लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं-बहनों का मजाक उड़ाना... किस तरह के लोग आजकल खुद को इंफ्लुएंसर बोल रहे हैं.. मैं पूछना चाहती हूं हमारा समाज कहां जाता जा रहा है? इस 2 मिनट के लिए फेम के लिए समाज कहां जा रहा है... ये हमें सोचना है। फडणवीस जी ने अच्छा कहा है, उनका मानना है जो हम कहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम किसी के बारे में जो कहते हैं, जब कानूनी तौर पर उसके बारे में पूछा जाएगा तो भी आप अपने स्टैंड पर कायम रहोगे? दूसरी तरफ, कंट्रोवर्सी के बावजूद कुणाल कामरा अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा- जो लोग सोशल मीडिया पर मेरा नंबर लीक करने या मुझे लगातार कॉल करने में बिजी हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब मेरे वॉयसमेल पर चला जाता है। जहां उन्हें वही गाना सुनाया जाएगा, जिससे वे नफरत करते ह। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर में छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने जो कहा, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं।

देश की इकलौती जगह, जहां के लोगों के पास है दो देशों की नागरिकता

जरा सोचिए, अगर आप अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं और आपकी नागरिकता बदल जाए, तो कैसा लगेगा? सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है! भारत और म्यांमार की सीमा पर एक ऐसा अनोखा घर है, जहां एक कमरे में आप भारतीय होते हैं और दूसरे में म्यांमार के नागरिक। यह अनोखा घर नागालैंड और म्यांमार के सागांग राज्य की सीमा पर स्थित है। सीमा पर होने के कारण इसका एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में आता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस घर का बेडरूम भारत में है और किचन म्यांमार में! यानी अगर आप यहां रहते हैं, तो आपकी चाय भारत में बन सकती है और आप उसे म्यांमार में बैठकर पी सकते हैं। यह घर गांव के मुखिया का है, जो दोनों देशों के बीच बसे इस अनोखे गांव के प्रधान भी हैं। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार, दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। इतना ही नहीं, ये लोग दोनों देशों में वोट भी डाल सकते हैं। यहां रहने वाले लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए किसी एक देश तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। वे दोनों देशों में जाकर काम कर पैसे कमा सकते हैं। इतना ही नहीं जो बच्चे भारतीय स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, वे भारत में पढ़ सकते हैं और जो म्यांमार की शिक्षा लेना चाहते हैं, वे म्यांमार शिक्षा ले सकते हैं। ठीक रोजगार के मामले में भी यही स्थिति है। गांव के लोग अपनी पसंद के हिसाब से दोनों देशों में काम कर सकते हैं। जिसे भारत में बेहतर अवसर मिलते हैं, वह भारत में काम करता है, और जिसे म्यांमार में, वह वहां काम करता है। बता दें, इस गांव के लोगों को फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत दोहरी नागरिकता मिली हुई है। यह गांव बिल्कुल सीमा पर बसा हुआ है। इसलिए यहां के लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने में कोई परेशानी न हो इसीलिए उन्हें यह विशेष सुविधा दी गई है। यही कारण है कि इस गांव के लोग भारत और म्यांमार, दोनों की संस्कृति को अपनाकर जीते हैं। उनके रीति-रिवाज, खान-पान और बोलचाल में दोनों देशों की झलक देखने को मिलती है। वे एक अनोखी पहचान के साथ रहते हैं, जहां सीमाएं उनके लिए कोई बाधा नहीं बनतीं और वे खुलकर अपना जीवन जी सकते हैं।

अजब-गजब | **सोचने को मजबूर कर देगा इस प्रश्न का उत्तर?**

हवाई जहाज में पैदा हुए बच्चों को किस देश की मिलती है नागरिकता

हमारा प्रश्न है कि आप विदेश जा रहे हों और हवाई जहाज के अंदर ही बच्चा पैदा हो जाए तो क्या होगा? किस देश के नागरिक कहलाएंगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जहां के माता पिता वहीं की नागरिकता। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं है। फिर क्या है सही जवाब? ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहता है? आखिर प्लेन में जन्में बच्चों की कैसे तय होती है नागरिकता? दरअसल, एक महिला के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। महिला सात माह की गर्भवती थी। उसके प्रेग्नेंसी की तारीख थोड़ी नजदीक आ रही थी। इस बीच एक दिन वह हवाई जहाज से यात्रा कर रही थी। प्रेग्नेंट महिला का नाम डेवी ओवेन था। डेवी आइवरी कोस्ट से लंदन जा रही थीं। इस दौरान उनके साथ सिर्फ चार साल की बेटी सफर कर रही थी। पति वहां मौजूद नहीं थे।

उड़ान के दौरान अचानक डेवी ओवन के पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जब बच्ची का जन्म हुआ तो विमान ब्रिटेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर था। अब वह बच्ची 28 साल की हो चुकी है और उसका नाम शोना है। वह दुनियाभर में उन लगभग 50 लोगों में से एक है, जिन्हें स्काईबॉर्न यानी आसमान में जन्में लोगों के नाम से जाना जाता है। बता दें कि हवाई

जहाज पर बच्चे को जन्म देना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहां हवा कम होती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। गंभीर समस्या यह है कि प्रसव के दौरान कोई समस्या आने या आपातकालीन सी-सेक्शन की जरूरत पड़ने की स्थिति में कोई उच्च तकनीक वाला उपकरण उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण से कुछ एयरलाइन्स 27 सप्ताह के बाद गर्भवती महिलाओं को ले जाने से मना कर देती हैं, जबकि अन्य एयरलाइन्स 40 सप्ताह तक की गर्भवती महिलाओं को मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ ले जाने की अनुमति देती हैं। अब सवाल यह है कि 36,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुए बच्चे को किसकी नागरिकता मिलेगी? विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लिए कोई एक नियम नहीं है। लेकिन याद रखें कि जिस देश से विमान उड़ान भर रहा है, वही देश उस विमान की भूमि या क्षेत्र माना जाता है। अधिकांश देश रक्त के आधार पर बच्चों को नागरिकता प्रदान करते हैं यानी बच्चे के माता-पिता जिस देश में होंगे, बच्चे वहां के नागरिक होंगे। लेकिन 1961 में एक एग्रीमेंट हुआ, जो ऐसे बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने में मदद करता है, जहां विवाद उत्पन्न होते हैं. यह एग्रीमेंट कहता है कि जिस देश की एयरलाइन उस देश की नागरिकता।

लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग का नियम तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसके अनुसार, यदि कोई बच्चा अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पैदा होता है, तो जन्म का स्थान समुद्र सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यदि वह विमान में पैदा हुआ है तो उसे हवाई शिशु माना जाना चाहिए।

विमान में बच्चे को जन्म देना वास्तव में माता-पिता और एयरलाइन दोनों के लिए अच्छी खबर है। एयरलाइन्स कंपनियां अपने प्रचार के लिए इसका व्यापक इस्तेमाल कर सकती हैं। वर्जिन ने एक बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुफ्त उड़ान का तोहफा दिया था, क्योंकि यह बच्चा उसके विमान में पैदा हुआ था। वहीं, ब्रिटिश एयरवेज ने प्लेन में जन्मी शोना को उसके 18वें जन्मदिन पर 2 टिकटें भेजीं, जिससे वह अपने दादी को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी।

बिहार में मिलकर लड़ेंगे चुनाव : खरगे

» आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से हुई चर्चा

कांग्रेस बोली- सीएम के चेहरे पर सामूहिक रूप से होगा फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति को पुख्ता करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सामूहिक निर्णय लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में बिहार को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और उनके पूर्ववर्ती अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे।

इनके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरु, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता मीरा कुमार, तारिक अनवर, शकील अहमद खान और मोहम्मद जावेद सहित कई नेता शामिल हुए। खरगे ने बैठक के दौरान कहा, बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है। बिहार के लोग विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और बेरोजगारी के कारण युवाओं में गुस्सा है।

विधान परिषद में अचानक राबड़ी पर बरस पड़े नीतीश

पटना। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में आरजेडी विधायकों द्वारा पहने गए बैज को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सीधा निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है, तुम चुप रहो। दरअसल, आरजेडी के विधान पार्षद हरे रंग के बैज लगाकर सदन में पहुंचे थे। इन बैजों पर लिखा था कि तेजस्वी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही उसे छीन लिया गया। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रास नहीं आई, क्योंकि जब 2023 में आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था, तब वे खुद सरकार का हिस्सा थे। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक आरजेडी विधायक को खड़ा किया। फिर मीडिया गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, यह तमाशा सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है!

नए कानून के जरिए आरक्षण को मिले संवैधानिक सुरक्षा : बारी

आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी फिर से आरक्षण बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाने की मांग करती है। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार से मांग की कि इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।

बेचारी पति के सहारे सत्ता में आई थीं : नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने आगे राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बेचारी तो अपने पति के सहारे सत्ता में आई थीं। उन्होंने 1997 का जिक्र करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सीबीआई ने आरोप तय किए, तो उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और परदे के पीछे से सत्ता चलाते रहे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आरजेडी के विधायकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने सदन के बाहर सीढ़ियों पर धरना देना शुरू कर दिया।

बजट हवा-हवाई, कोई आधार नहीं

» आतिशी बोलीं - सरकार के पास इतना रेवेन्यू आ रहा होता तो वह आर्थिक सर्वेक्षण सदन में जरूर रखती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मंगलवार को पेश किए गए बजट को हवा-हवाई करार दिया। आतिशी ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के बजट का कोई भी आर्थिक विश्लेषण में आधार नहीं है। अगर सरकार के पास वास्तव में एक लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू आ रहा होता तो वह आर्थिक सर्वेक्षण सदन में जरूर रखती। इससे पहले रेखा सरकार ने दिल्ली के लिए खजाना खोला दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य महोत्सव, संगीत समारोह जैसे कार्यक्रमों के साथ वार्षिक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन होगा।

पर्यटन के क्षेत्र में नई प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना है। मैथिली-भोजपुरी अकादमी के लिए बजट आवंटन 3.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

आप सरकार ने शीश महल बनाया : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे और उनके (आम आदमी पार्टी) बीच बहुत अंतर है। आपने (आप) अपने लिए शीशमहल बनाया। हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। आपने लाखों रुपये की टॉयलेट की सीट लगवाई, हम झुग्गी-बस्तियों में लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे।

मप्र में मंत्री ने बताई गलत जाति : अहिरवार

» कांग्रेस का आरोप- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमाण पत्र को बताया फर्जी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मप्र शासन में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाया है। अहिरवार ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच नहीं कराती है कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

उन्होंने कहा कि सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से प्रतिमा बागरी विधायक हैं, वह अनुसूचित जाति (अजा) के लिए आरक्षित है। लेकिन तथ्य यह है कि बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में रहने वाले 'बागरी' जाति के लोग मूल रूप से ठाकुर (राजपूत) समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते।

इसके बावजूद, प्रतिमा बागरी एवं इनके परिवार ने प्रशासनिक मिलीभगत से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और मंत्री पद हासिल कर लिया, जो संविधान और सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। अहिरवार ने कहा कि 1961 व 1971 की जाति जनगणना में पन्ना, सतना और सिवनी जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल नहीं थी। जाति छानबीन समीति मध्य प्रदेश के 2003 निर्णय एवं 2007 भारत सरकार के राजपत्र के सरकारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि राजपूत समुदाय के 'बागरी' जाति के लोग अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकते। इसके बावजूद, कुछ लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरियों और चुनावी आरक्षण का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिमा बागरी भी इसी प्रक्रिया के तहत गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विधायक और मंत्री बनी हैं।

निष्पक्ष जांच कराकर की तत्काल बर्खास्त की मांग

अहिरवार ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की कि प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त कर, वास्तविक अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए एवं विधायक पद से इस्तीफा लेकर पुनः उप चुनाव कराया जाए।

जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे केकेआर-राजस्थान

» दोनों टीमों को अपने पहले मुकाबले में मिली थी हार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी। हार के साथ आईपीएल सीजन की शुरुआत करने वाली केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की टीम की नजरें जीत की पटरी पर लौटने पर होगी। कोलकाता को आरसीबी से जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान से हार मिली थी। राजस्थान और केकेआर के बीच बराबरी का मुकाबला है। दोनों टीमों के हेड टु हेड की बात करें तो राजस्थान और केकेआर के बीच आईपीएल में अब तक कुल 29 मैच हुए हैं जिसमें ने दोनों ही टीमों ने 14-14 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है।

राजस्थान और कोलकाता की टीमें इस सीजन अपने पहले मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में आक्रामकता दिखाने में असफल रही। दोनों टीमें अब वापसी करना चाहेंगी। कागजों में केकेआर का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग की भी परीक्षा होगी क्योंकि पहले मैच में वह कुछ फैसले करते हुए असमंजस की स्थिति में दिखे। केकेआर के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय है। केकेआर को उम्मीद होगी कि वरुण राजस्थान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करें। राजस्थान की टीम को अगर वापसी करनी है तो उसके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सनराइजर्स के खिलाफ पिछले मैच में उसके मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चार ओवर में 76 रन लुटाए, जबकि फजल हक फारूकी और महेश थीक्षाना भी बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पाए थे।

रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को 11 रन से हराया

अहमदाबाद। डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह और विजयकुमार विशक की घातक गेंदबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह की 81* रनों की साझेदारी की बदौलत 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 243 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम निर्धारित ओवरों में पांच विकेट खोकर सिर्फ 232 रन ही बना सकी। बता दें 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद मोर्चा जोस बटलर और साई सुदर्शन ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी हुई, जिसे अर्शदीप सिंह ने तोड़ा।

भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले भाजपा सरकार में ये क्या हो रहा है!

कारोबारियों ने तीन युवतियों के साथ पार कीं दरिंदगी की हदें! नंगा कर कराते थे डांस... जबरन पिलाते थे बीयर

» नौकरी के नाम पर युवतियों के साथ हो रहा था यौन शोषण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बांदा। भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले बीजेपी राज वाले यूपी में समाज में व्यवस्था तार-तार हो रही है। कहीं हुड़दंगी छात्रों को टोकने पर महिला को गोली मार दी रही है तो कहीं पत्नी पति के टुकड़े-टुकड़े कर रही है तो कहीं अबोध बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है। समाज व सरकार धर्म के नाम पर सियासत में फंसी हुई हैं।

बतादें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बांदा में तीन युवतियों का यौन शोषण किया गया। आरोप कारोबारियों पर लगा है। तीन कारोबारियों पर नौकरी देने के बहाने उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। वहीं, मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। तीन

युवतियों के साथ करते थे दुष्कर्म

युवतियों के मुताबिक, इंटरनेट में वीडियो प्रचलित करने की धमकी से तीनों बुरी तरह से डर गई थी। उनकी सहेली, जोकि अनुसूचित जाति है, उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। यह भी आरोप लगाया है कि तीनों आरोपी उन्हें निर्वस्त्र करके डांस कराते थे। जबरन बियर और सिगरेट पिलाते थे। जब तीनों नशे में हो जाती थीं, तो उनके साथ दुष्कर्म करते थे। यह भी आरोप लगाया है कि तीनों रईसजादों ने और भी लड़कियों को शिकार बनाया है, लेकिन वह बदनामी के डर से सामने नहीं आ रही हैं।

मेडिकल व बयान आज लेगी पुलिस

पीड़िताओं ने साधी चुप्पी शहर की तीन युवतियों की ओर से यौन शोषण की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद से उनके घरवालों ने चुप्पी साध ली है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद युवतियां भी सामने नहीं आ रही हैं। पीड़िताओं और उनके घरवालों से बात करने का प्रयास किया गया तो एक पीड़िता के घरवालों ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया, जबकि दो पीड़िताएं फोन नहीं उठा रही हैं। युवतियों की ओर से दी गई पेन ड्राइव और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। विवेचना सीओ सिटी कर रहे हैं। पीड़िताओं के मेडिकल और बयान दर्ज कराने कार्रवाई की जा रही है।- **अंकुर अग्रवाल**, एसपी, बांदा।

एक कारोबारी ने आरोपों को बताया गलत, दो ने चुप्पी साधी

एक आरोपी ऑटो पार्ट्स व्यापारी व जिला परिषद चौराहा निवासी आशीष अग्रवाल का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्हें फर्जी फंसाया गया है। वह पीड़ितिाओं को जानते तक नहीं हैं। दूसरे आरोपी गुटखा व्यवसायी स्वतंत्र साहू और ठेकेदार लोकेंद्र सिंह चंदेल ने मोबाइल फोन बंद कर रखा है। तहरीर में चौथे व्यक्ति अलीगंज मोहल्ला निवासी नवीन का जिक्र किया है। उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।

युवतियों के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने अब तक न तो मेडिकल परीक्षण कराया न बयान दर्ज कराए हैं। मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह का कहना है कि पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण बुधवार को कराया जाएगा। साथ ही मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। सवाल यह है कि जब पहले ही दिन युवतियों ने पेन ड्राइव में सबूत सौंप दिए थे, तो पुलिस कार्रवाई में इतनी देरी क्यों कर रही है? जानकारी के अनुसार, तीन युवतियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर शहर के तीन कारोबारियों पर कोतवाली थाने में 22 मार्च को यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी

» नहीं कम हो रहीं छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम की मुश्किलें

» 6000 करोड़ के महादेव एप घोटाले के मामले में दबिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के आवास पर बुधवार को सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची। बताया जा है कि सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई में जांच करने पहुंची है। इससे पहले ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। दबिश कथित 6,000 करोड़ रुपये के महादेव एप घोटाले के सिलसिले में की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की टीमों ने रायपुर और भिलाई में बघेल के आवास के साथ-साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी की। सीबीआई की टीम घर के अंदर जांच कर रही है और घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे एवं अन्य के परिसरों पर 10 मार्च को छापेमारी की थी। सीबीआई की छापेमारी के लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद (गुजरात) में होने वाली कांग्रेस की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है।

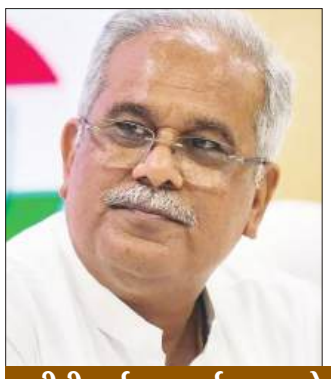

पूरी तरह से बौखला गई है भाजपा : सुशील आनंद

कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, इससे पहले उन्होंने (भाजपा ने) उनके आवास पर ईडी को भेजा था। आज सीबीआई भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास पर आई है। उनका आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में खलल डालने के लिए भाजपा ने आज उनके आवास पर सीबीआई की टीम भेजी है। भाजपा बौखला गई है क्योंकि वह राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है।

सीबीआई बन गई धमकाने का हथियार : टीएस सिंह देव

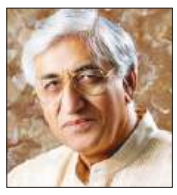

बघेल के यहां छापे पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बार-बार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सेंट्रल जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाना निंदनीय है। टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा, बार-बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय है। ये केवल भूपेश जी छवि को खराब करने की भाजपा की नाकाम कोशिश है। प्रदेश की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है, इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दों से का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे लिखा, पहले ईडी फिर सीबीआई जांच एजेंसियों को भाजपा की बी टीम बन कर काम करने से फुर्सत ही नहीं है। अभी हाल में ईडी द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की रिपोर्ट खुद सरकार को जब दिखानी पड़ी तो निश्चित हो गया कि यह केवल धमकाने और परेशान करने का हथियार बना हुआ है। भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही यह कार्रवाई लोकतंत्र का हनन है।

राजनीति से प्रेरित : बाजवा

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, यह राजनीति से प्रेरित है, पहले भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा और आज सीबीआई का। इसका साफ मतलब है कि भाजपा केवल कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है, मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि इन चीजों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल न करें।

बघेल के आवास के बाहर जुटे समर्थक

भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और चार आईपीएस अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव, एसपी आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा सहित दो सिपाही नकुल-सहदेव के घर सीबीआई ने छापा मारा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में टीम ने दबिश दी है. जानकारी के मुताबिक सीबीआई की 10 से अधिक टीमें 26 मार्च की तड़के रायपुर से निकली थीं। एक टीम रायपुर स्थित भूपेश बघेल के घर पहुंची।

संसद में नेता प्रतिपक्ष व स्पीकर में रार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। मंगलवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मेरी अपील है कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। स्पीकर उठे और एकदम से चले गए और सदन स्थगित कर दिया। नेता विपक्ष को बोलने का समय दिया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जगह होती है, लेकिन विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को सदन में नियमों के तहत आचरण करने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत सदन को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

» स्तन पकड़ना और लड़की की सलवार की डोरी खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं वाले फैसले को पलटा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संवेदनहीनता को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल उत्पीड़न के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें न्यायाधीश ने कहा था कि स्तन पकड़ना और पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार के प्रयास के बराबर नहीं है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ और उन्होंने इस मामले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला अचानक नहीं लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया, इसलिए इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसले के लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। यह अचानक नहीं लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया। इस प्रकार, इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन चूंकि पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए हम इन टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से सहमति जताते हुए कहा कि कुछ फैसलों में उन्हें रोकने के कारण होते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, यह एक गंभीर मामला है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।